रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102024-257943
CG-DL-E-24102024-257943

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4132] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/आश्विन 22, 1946
No. 4132] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASVINA 22, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4495(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भामरागढ़ वन्यजीव अभयारण्य, महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1175 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1175 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की सूचना से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड

(xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1175 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित पैरे रखे जाएगे, अर्थात्: -

"**5. मनीटरी समिति.** – केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली एक मनीटरी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

i.	गढ़चिरौली जिले के कलेक्टर	अध्यक्ष, पदेन;
ii.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), अल्लापल्ली	सदस्य, पदेन;
iii.	महाराष्ट्र सरकार के राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास विभाग का एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
iv.	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा हर तीन साल में समय-समय पर नामनिर्दिष्ट किया जाता है।	सदस्य;
v.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को हर तीन साल में समय-समय पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
vi.	प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
vii.	सदस्य-सचिव या सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
viii.	वरिष्ठ नगर नियोजक, बुलढाणा	सदस्य, पदेन;
ix.	उप वन संरक्षक (टी)- भामरागढ़	सदस्य सचिव, पदेन।

(2) मनीटरी समिती, वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी मे यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय,आने वाले और उस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, उपपैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों,जिन्हे सम्मिलित नहीं किया गया है और जो पारिस्थिकी संवेदी ज़ोन मे आते हैं, की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मनीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मनीटरी समिती का वास्तविक सदस्य-सचिव या सम्बद्ध कलेक्टर या सम्बद्ध उप वन संरक्षक,ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

IndiCode

(5) मनीटरी समिती, प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या सम्बद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सह्यता के लिए,आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मनीटरी समिती, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संलग्न **उपाबंध-IV** में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, उस वर्ष की 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(7) केंद्रीय सरकार, मनीटरी समिती को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए, लिखित में ऐसे निर्देश दे सकेगी,जो वह उचित समझे।

[फा.सं. 25/12/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी'

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1175 (अ), तारीख 12 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2024

S.O. 4495(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bhamragarh Wildlife Sanctuary, Maharashtra in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1175(E), dated the 12th April, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1175(E), dated the 12th April, 2017;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1175(E), dated the 12th April, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5, the following paragraph shall be respectively substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee consisting of the following persons, namely:-

(i)	The Collector of Gadchiroli District	Chairman, *ex-officio*;
(ii)	The Deputy Conservator of Forests (Wildlife), Allapalli	Member, *exofficio*;
(iii)	A representative each of Department of Revenue, police, Public Works Department, Industries, Water Resources, Urban Development, Rural Development of Government of Maharashtra	Member, *exofficio*;

(iv)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member;
(v)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra from time to time every three years.	Member;
(vi)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board	Member, *exofficio*;
(vii)	Member-Secretary or Member, State Biodiversity Board	Member, *exofficio*;
(viii)	The Senior Town Planner, Buldhana	Member, *exofficio*;
(ix)	Deputy Conservator of Forests (T)- Bhamragarh	Member Secretary *exofficio*."

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-IV.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

[F. No. 25/12/2015-ESZ-RE]

DR. S. KERKETTA. Scientist "G"

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1175(E), dated the 12th April, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA